आकाशवाणी शिमला

02.12.2025 / प्रादेशिक समाचार / 18:00 बजे

प्रश्नकाल

हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य पथ परिवहन निगम में युक्तिकरण कर घाटे वाले 4 सौ 35 बस रूट बंद करेगी। धर्मशाला के तपोवन में चल रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक संजय अवस्थी के एक सवाल पर हस्तक्षेप करते हुए ये बात कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एचआरटीसी को हर माह 70 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। इस तरह निगम का सालाना घाटा 8 सौ 40 करोड़ रुपए है और यह घाटा बढ़कर अब तक 2 हजार 2 सौ करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार परिवहन निगम को हर साल 7 सौ 80 करोड़ रुपए अनुदान दे रही है और निगम के बढ़ते घाटे को देखते हुए सरकार कुछ रूटों को बंद कर उन्हें निजी क्षेत्र में देने जा रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार ने परिवहन निगम के वही रूट बंद किए हैं, जहां अतिरिक्त बसें चल रही थी और घाटे में थी। इससे पहले, मूल प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि कंधर–बागा बस सेवा को फिलहाल चंडीगढ़ तक ही चलाया जाएगा और इसे फिर से दिल्ली के लिए बहाल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम पर इस समय 13 सौ करोड़ रुपए से अधिक की देनदारी है।

नियम 130

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार के तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के मौके पर मंडी में प्रस्तावित जश्न को सरकार का अमानवीय दृष्टिकोण करार दिया है। विधानसभा में आज आपदा पर नियम 130 के तहत हो रही चर्चा में हिस्सा लेते हुए उन्होंने सरकार से मंडी में सेलिब्रेशन के सभी कार्यक्रम रद्द करने की मांग की और कहा कि सरकार बेवजह पैसा खर्च न करे। उन्होंने कहा कि इसके बजाय यह पैसा आपदा पीड़ितों के राहत व पुनर्वास पर खर्च किया जाए। जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि हिमाचल को केंद्र से आपदा राहत के लिए अभी तक 5 हजार 2 सौ 50 करोड़ रुपए की राशि मिल चुकी है। जयराम ठाकुर ने राज्य के आने वाले बजटों में आपदा के लिए अलग से धनराशि का प्रावधान करने की मांग की। उन्होंने सरकार पर आपदा के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य में डिजास्टर एक्ट लागू है, लेकिन सरकार उसके अनुरूप कार्य नहीं कर रही है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 15 सौ करोड़ रुपए के राहत पैकेज को इसलिए राज्य सरकार के खाते में मांग रही है ताकि वह इस पैसे से वेतन–भत्ते दे सके और सरकार चलाने के लिए इस पैसे को खर्च कर सके।

नियम 130–2

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चर्चा में दखल देते हुए कहा कि सरकार मंडी में सत्ता में तीन साल पूरा होने पर जश्न नहीं, बल्कि जन संकल्प रैली आयोजित कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की इस जन संकल्प रैली पर डिजास्टर फंड से कोई पैसा खर्च नहीं होगा और रैली का सारा खर्च राज्य सरकार के खजाने से दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जन संकल्प रैली पर कम से कम खर्च करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने आपदा राहत में कोई भेदभाव नहीं किया है। उन्होंने इसके लिए भाजपा से भी सहयोग मांगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला के जोरावर मैदान में भाजपा को विरोध रैली आयोजित करने की अनुमति नहीं दिए जाने का बचाव करते हुए कहा कि भाजपा ने इस रैली में 10 से 12 हजार लोगों की भीड़ आने का दावा किया है, जबकि इस मैदान की क्षमता सिर्फ तीन से चार हजार लोगों की ही है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में सरकार रैली की अनुमति देती है तो इतनी भारी भीड़ के कारण भगदड़

मच सकती है और सरकार ऐसी स्थिति नहीं बनने देना चाहती। उन्होंने यह भी कहा कि इसके बावजूद भाजपा इस मैदान की अनुमति के लिए आवेदन करे, फिर सरकार तय करेगी कि अनुमति देनी या नहीं।

सिल्क एक्सपो

शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में आयोजित राष्ट्रीय सिल्क एक्सपो में पारंपरिक साड़ियां लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। 18 दिसम्बर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में देश भर के बुनकर अपनी कला और परंपरा से जुड़े खास उत्पाद लेकर पहुंचे हैं। इस प्रदर्शनी के कोऑर्डिनेटर जितेंद्र चोपड़ा ने बताया कि केंद्र सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस प्रदर्शनी में करीब 35 स्टोल लगाए गए हैं।

———————————————————————————